सतत विकास के लिए अहम है ऊर्जा दक्षता

संदर्भ

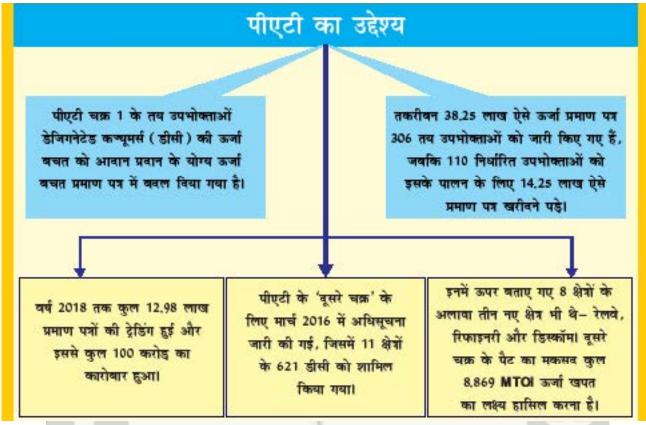
- भारत में व्यापक स्तर पर घरों का विद्युतीकरण हुआ है और जाहिर तौर पर ऊर्जा के लिए मांग में भी बढ़ोतरी हुई है। इसका एक प्रमुख कारण तेजी से बढ़ रही आबादी है। एक और वजह ऊर्जा संबंधी आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी है। चूंिक ऊर्जा के परंपरागत साधन कम हो रहे हैं और अक्षय ऊर्जा के साधन विकासशील दौर में हैं, लिहाजा सभी स्तरों पर ऊर्जा दक्षता में सुधार करना इस समस्या से निपटने का तात्कालिक समाधान है।
- नोट:- यह बात ध्यान देने योग्य है कि ऊर्जा, पर्यावरण और सतत विकास के बीच सीधा संबंध है।
- सतत विकास चाहने वाले देश को आदर्श और जरूरी तौर पर ऊर्जा के उन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, जिसका पर्यावरण पर कम से कम बुरा असर होता है।
- ऊर्जा दक्षता में बढ़ोतरी के जिरये पर्यावरण संबंधी उत्सर्जन और उसके बुरे असर के मामले में सतत विकास की सीमा संबंधी चिंताओं से निपटा जा सकता है।
- सरकार ने राष्ट्रीय निर्धारित योगदान के जिरये उत्सर्जन तीव्रता को कम कर साल 2030 तक इसे 2005 के स्तर की तुलना में जीडीपी का 33-35 फीसदी तक कम करने का लक्ष्य तय किया है।

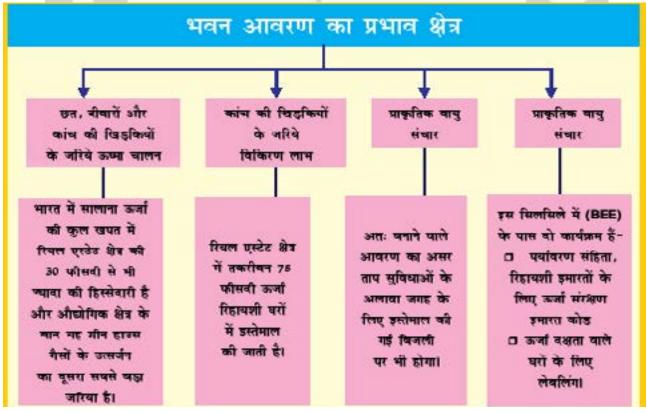
इस लक्ष्य को हासिल करने के मकसद से खास तौर पर 3 क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए समेकित प्रयास करने की जरूरत है।

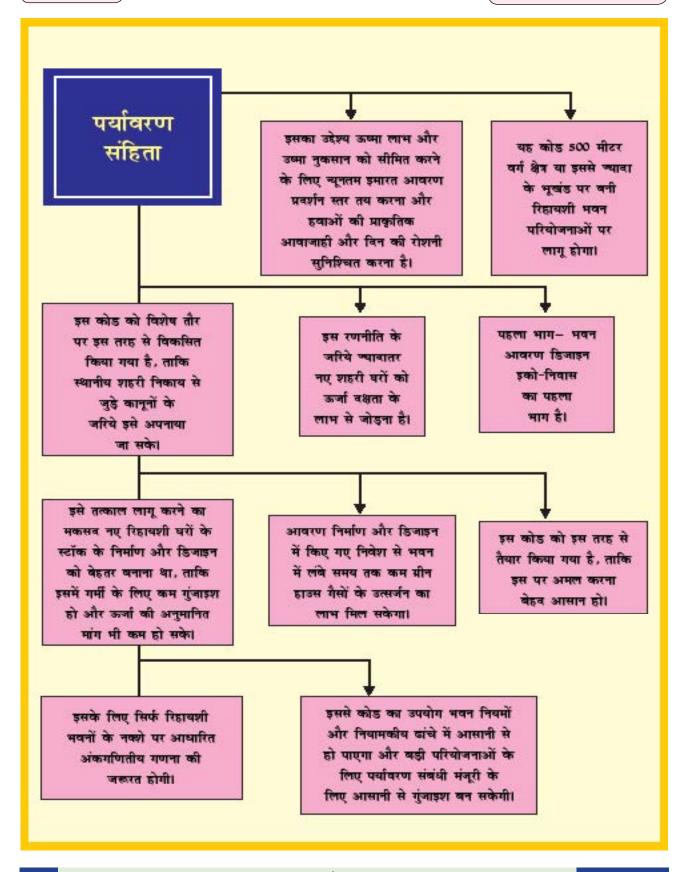


- औद्योगिक क्षेत्र अब भी सबसे ज्यादा ऊर्जा खपत करने वाला क्षेत्र है, जहां ऊर्जा संरक्षण की अहम भूमिका होगी।
- प्रमुख उद्योगों में किफायती स्तर पर ऊर्जा की खपत यानि ऊर्जा संरक्षण और तकनीकी बेहतरी के लिए काफी संभावनाएं हैं।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ऊर्जा दक्षता में सुधार के मकसद से राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता बढ़ोतरी मिशन (एनएमईईई) के तहत पीएटी-परफॉर्म, एचीव एंड ट्रेड यानि (प्रदर्शन करें, हासिल करें और व्यापार करें) योजना लागू कर रहा है।









ऊर्जा दक्षता वाले घरों के लिए लेबलिंग कार्यक्रम

- 💠 उपभोक्ताओं को अक्षय ऊर्जा के नजरिये से भवनों की तुलना करने में सक्षम बनाने के लिए व्यापक लेबलिंग कार्यक्रम महत्वपूर्ण है।
- ऊर्जा लेबल उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष, भरोसेमंद और सस्ती जानकारी वाले प्रावधान के माध्यम से बेहतर फैसले लेने में मदद करते हैं। प्रस्तावित लेबलिंग कार्यक्रम का मकसद में बताया गया है।
- 💠 इससे पूरे देश में ऊर्जा दक्षता की स्थिति को बेहतर कर बड़े पैमाने पर ऊर्जा की बचत होने का अनुमान है।
- ❖ प्रस्तावित लेबिलंग कार्यक्रम के जिरये साल 2030 तक तकरीबन 388 बीयू ऊर्जा की बचत की संभावना है।
 - यह ऊर्जा दक्षता से जुड़े बाजार और तकनीक को बढ़ावा देने के लिए आधार का काम करेगा।
 - ऊर्जा दक्षता का लेबल हासिल करने के मकसद से उपभोक्ता ऊर्जा दक्षता वाली सामग्री की मांग करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को इस तरह की सामग्री के उत्पादन का ज्यादा अवसर मिलेगा।
- लेबलिंग प्रणाली के लागू होने के बाद आवासीय मूल्य शृंखला अतिरिक्त संख्या में पेशेवरों को आवासीय लेबल अनुदान की प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
- यह भारत में सामग्री विनिर्माताओं को ऊर्जा के लिहाज से दक्ष सामग्री के निर्माण के लिए भी प्रेरित करेगी।

कार्यक्रम के लाभ

- लेबलिंग प्रणाली ऊर्जा खर्च में भी कटौती के लिए गुंजाइश बनाएगी।
- उपभोक्ता के पास खर्च करने योग्य आय ज्यादा होगी, जिसे अन्य चीजों पर खर्च किया जा सकता है, भविष्य की आपातकालीन जरूरतों के लिए बचाकर रखा जा सकता है या नकदी पैदा करने वाली संपत्तियों को तैयार करने के मकसद से निवेश किया जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक सतत विकास उन लक्ष्यों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी, जिसका मकसद किफायती और स्वच्छ ऊर्जा पैदा करना है।

उपभोक्ता उपकरण

 उपभोक्ता उपकरण ऊर्जा की खपत से जुड़ा अहम क्षेत्र है। इसके दायरे में एसी, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन आदि जैसे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं।

- 💠 टिकाऊ उपभोक्ता सामग्री क्षेत्र में ऊर्जा की बचत संबंधी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं।
- 🍫 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) एयर कंडीशनरों के लिए अधिकतम तापमान सेटिंग के जरिये ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा दे रहा है।
- बीईई के अध्ययन के मुताबिक, एसी तापमान सेटिंग में एक डिग्री की बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप बिजली की खपत में
 6 फीसदी की कमी आती है।
- ❖ ऊर्जा की बचत और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए 24-26 डिग्री सेल्सियस की डिफॉल्ट सेटिंग की सिफारिश की गई है।
- माइक्रोवेव ओवन घरों में काफी लोकप्रिय होता जा रहा है और इसमें ऊर्जा दक्षता और बेहतर तकनीक को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।
- स्टार रेटिंग वाले माइक्रोवेव ओवन और वॉशिंग मशीन को अपनाकर साल 2030 तक 3 अरब यूनिट से भी ज्यादा बिजली की बचत करने का अनुमान है।
- इस तरह से इन उपायों के जिरये साल 2030 तक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में 24 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो
 सकती है।

सौर संभावनाओं को हासिल करने के उपाय

सरकार का लक्ष्य

भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

इसमें सबसे ज्यावा हिस्सेवारी यानि 100 गीगावाट सौर ऊर्जा के लिए तय की गई है।

इस क्षेत्र में ज्यावा से ज्यावा खिलाड़ियों को आकर्षित करने या और क्षमता बढ़ाने के लिए कई कवम उठाए गए हैं।

पिछले कुछ वर्षों में हम पहले ही 28 गीगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता हासिल कर चुके हैं, जबकि इससे जुड़ा सीएजीआर 55 फीसवी है।

भारत में सौर कर्जा उद्योग को अगले स्तर पर ले जाने के लिए यहां 5 ऐसे क्षेत्रों के बारे में बताया जा रहा है, जिस पर विशेष ध्यान वेने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को शुरू करना इस क्षेत्र को मजबूत बनाने की विशा में अहम कवम था।

सौर पार्कों के गठन, वायिविलिटी गैप फंडिंग, संबंधी मदद, और कुसुम (कृषि के लिए सौर ऊर्जा क्षमता के इस्तेमाल का मकसद) और सृष्टि (छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित) जैसी योजनाओं की पेशकश के जरिये सरकार ने सौर उद्योग की रफ्तार को तेज करने को लेकर उत्सुकता दिखाई है।

भारत में सौर कर्जा की संभावनाओं को पूरी तरह से हासिल करने के लिए सामरिक स्तर पर और उपाय किए जाने की जरूरत है और 2022 तक 100 गीगावाट सौर कर्जा क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए जमीनी स्तर पर व्यापक काम करने की जरूरत है।

समसामियक संदर्भ

- भारत की विशाल आबादी की जरूरतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। हालांकि, संसाधनों का जस का तप बने रहना तेज रफ्तार वाली अर्थव्यवस्था की बढ़ रही मांगों को पूरा करने के लिए शायद पर्याप्त नहीं हो। उदाहरण के लिए हम ऊर्जा क्षेत्र की बात करते हैं।
- देश में बिजली की प्रति व्यक्ति की खपत 1,100 किलोवाट सालाना है, जो अमेरिका और चीन जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले काफी कम है।
- 💠 शहरीकरण और औद्योगिकरण विकास की बढती दरों के साथ बिजली की मांग में भी तेजी निश्चित है।
- 💠 ऊर्जा के क्षेत्र में क्षमता को बढ़ाकर मांग-आपूर्ति के इस अंतर को दर करना नीति निर्माताओं के लिए प्राथमिकता सूची में ऊपर है।

तकनीक

- भारत में सौर ऊर्जा देश की ऊर्जा जरूरतों का प्रमुख क्षेत्र बनकर उभर रहा है, लेकिन अभी भी इस सिलिसिले में बड़ी खाई को पाटा जाना बाकी है।
- ❖ उदाहरण के तौर पर छत पर मौजूद रहने वाली सौर ऊर्जा वाली प्रणाली में बड़े स्तर पर क्षमता बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए संबंधित राज्य सरकारों से सहयोग जरूरी है।
- इस क्षेत्र में नई-नई तकनीक, मसलन फ्लोटिंग सोलर और बीआईपीवी (भवन की छतों और आवरण के लिए इस्तेमाल की गई पारंपरिक सामग्री के बदले फोटोवोलटइक सिस्टम का विकल्प) सौर ऊर्जा संबंधी क्षमताओं को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
- इस क्षेत्र में बड़ी संभावना को देखते हुए सरकार और निजी इकाइयां, दोनों को शोध और विकास पर जोर देकर इसके लिए जरूरी
 मदद मुहैया कराना चाहिए और इस क्षेत्र से जुड़ी नई तकनीक और नवाचार को तेजी से अपनाना चाहिए।
- इससे न सिर्फ इसके लिए भिवष्य की दिशा तय करने में मदद मिलेगी, बिल्क इसकी लागत को भी कम करना मुमिकन हो सकेगा।
 जाहिर तौर पर ऊर्जा के इस माध्यम को अपनाने की प्रक्रिया तेज होगी।

नीतिगत समर्थन

- तकनीकी विकास और सरकार की नीति के कारण पिछले कुछ साल में सौर ऊर्जा की दरों में कमी आई है और इस तरह से ऊर्जा के इस माध्यम की पहुंच आम लोगों तक बढ़ी है।
- 💠 हालांकि, हाल के वर्षों में सौर ऊर्जा संबंधी दरों का मार्जिन कम हुआ है, जिससे मुनाफा भी कम हुआ है।
- इसकी दरें ऊर्जा के अन्य साधनों के मुकाबले बेहद कम हैं और इसे देखते हुए बेहतर दरों की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है, तािक इस क्षेत्र के नए, खिलािंडियों के लिए टिकाऊ कारोबारी मॉडल बन सके और इसमें पूंजी निवेश बढ़ने की राह आसान हो सके।
- इससे आखिरकार आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी और आम आदमी के लिए कीमतें भी कम होगी।
- 💠 संबंधित राज्य सरकारों को क्षमता में नियमित बढ़ोतरी के साथ सौर ऊर्जा उत्पादन की दर के बारे में बताना चाहिए।

डिस्कॉम (वितरण कंपनियों) की आर्थिक हालत

- विद्युत वितरण कंपनियों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार की पहल के बावजूद पिछले कुछ वर्षों में राज्य विद्युत वितरण कंपनियों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।
- 💠 ये वितरण कंपनियां ऊर्जा उत्पादन के चक्र में अहम कड़ी हैं और पूरी प्रक्रिया में इनका असर है।
- 💠 अत: वितरण कंपनियों को ठीक स्थिति में रखना साल 2022 से जुड़े लक्ष्य की अहम कड़ी है।
- सरकार को अक्षय ऊर्जा तकनीक का कुल मूल्य वसूलने के मकसद से सहायक बाजारों के संचालन की खातिर नीतियां भी बनानी चाहिए।

वित्तीय सुधार

- 💠 अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को मदद करने में बैंकिंग प्रणाली में सुधार दीर्घकालिक कदम होगा।
- फिलहाल, बैंकों ने विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर जो श्रेणी बना रखी है, उसके तहत बैंक अक्षय ऊर्जा को ऊर्जा क्षेत्र के एक छोटे से हिस्से के तौर पर देखते हैं और ज्यादातर बैंकों में कर्ज का अधिकांश हिस्सा ताप संयंत्रों के पास चला जाता है।
- इस तरह से फंड का महज छोटा सा हिस्सा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए बचता है। हालांकि, वास्तविकता यह है कि अक्षय ऊर्जा ने जबरदस्त बढ़ोतरी हासिल की है और सरकारी खजाने में राजस्व लाने में उसका शानदार योगदान रहा है।

निर्माण IAS

- 💠 सरकार अक्षय ऊर्जा के रणनीतिक महत्त्व को देखते हुए इसे कर्ज के मामले में प्राथमिकता वाले क्षेत्र का दर्जा भी दे सकती है।
- भविष्य में अलग-अलग तरह के बॉन्ड मार्केट स्वच्छ ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं के लिए किफायती दर पर फंड उपलब्ध कराने में मददगार होंगे।
- सरकार को बैंकिंग प्रणाली को साफ-सुथरा बनाने का अपना मिशन जारी रखना चाहिए और उसे बैड लोन की समस्या को भी हल करने में बैंकों की मदद करनी चाहिए।
- 💠 साथ ही, बैंकों के कर्ज देने संबंधी नियम की भी समीक्षा होनी चाहिए, ताकि इसे कम सख्त बनाया जा सके।
- 💠 एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सस्ती दरों पर ज्यादा फंड मुहैया करा सकेगी।

करोबार में सुगमता (ईज ऑफ डुइंग बिजनेस) के लिए गुंजाइश बनाना

- सुधारों के लिए सरकार के अभियान ने भारत में निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है।
- ❖ पिछले कुछ साल में ईज ऑफ डूंइंग बिजनेस रैंक में हमारी लगातार बेहतर होती स्थिति से भी यह पता चलती है।
- बहरहाल, पूरे वैल्यू चेन (मूल्य शृंखला) में पिरयोजनाओं पर काम करने के लिए जल्द से जल्द मंजूरी (खासतौर पर जमीन संबंधी बदलाव की मंजूरी) अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए काफी मददगार होगी।
- सरकार को ज्यादा मजबूत ट्रांसिमशन प्रणाली बनानी चाहिए। यह न सिर्फ निवेशकों के भरोसे को बढ़ाएगा, बिल्क विद्युत वितरण के दौरान नुकसान भी रोकेगा।
- साल 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के वित्त प्रदाताओं, डिस्कॉम और निजी खिलाडि्यों समेत तमाम संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयासों की जरूरत होगी।
- 💠 सौर ऊर्जा उद्योग के विकास में बुनियादी बदलाव में सरकार को अहम भूमिका निभानी होगी।

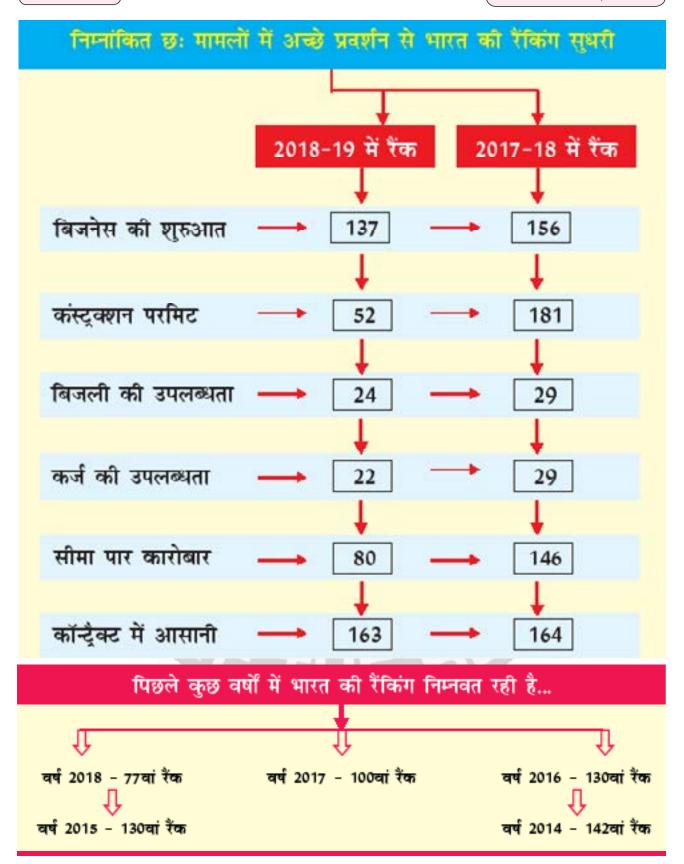
सरकार को न सिर्फ जरूरी नीतिगत मदद मुहैया कराकर बल्कि विभिन्न संबंधित पक्षों का मुख्य समन्यवक बनकर भी इस भूमिका का निर्वहन करना होगा।

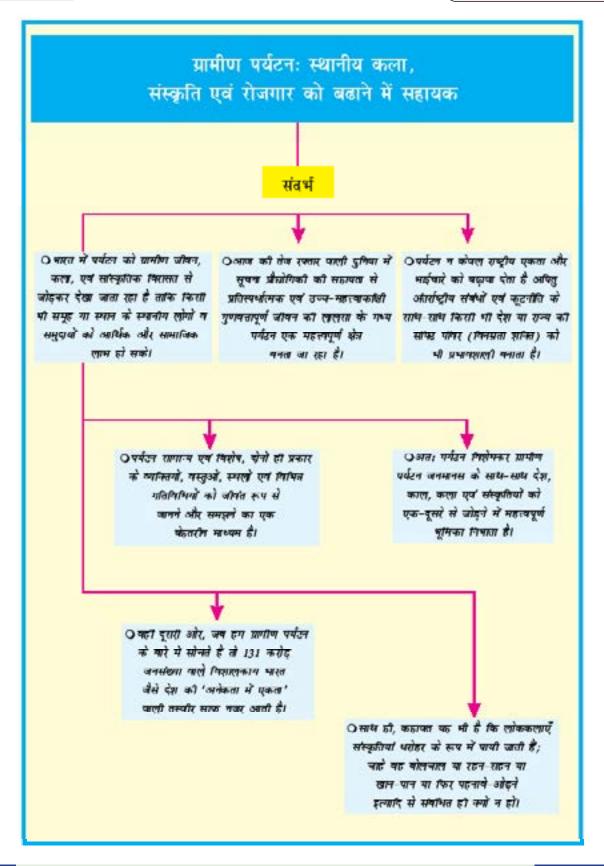
ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस रैंकिंग क्या होती है?

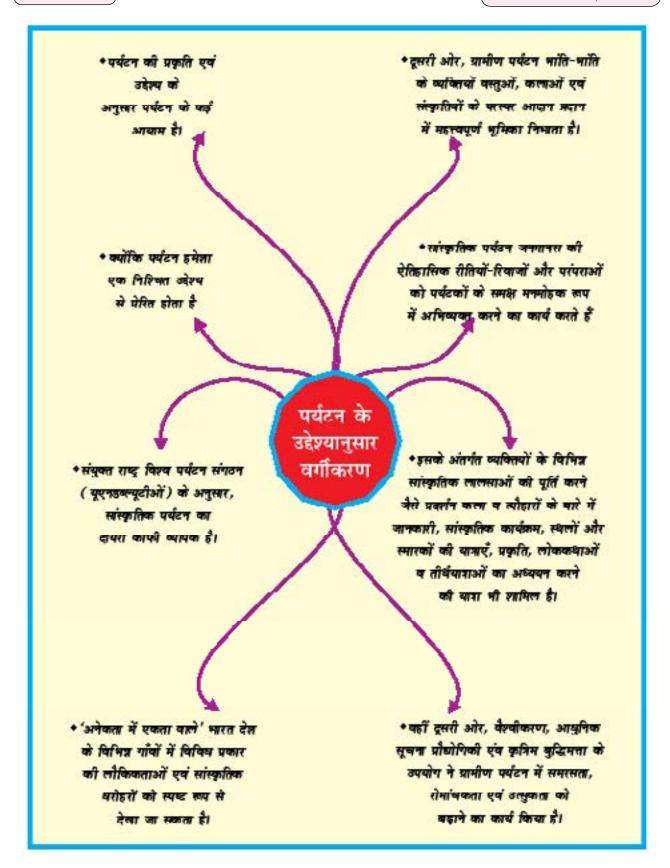
- उद्योग सहजता सूचकांक विश्व वैंक द्वारा जारी की जाने वाली सूचकांक है।
- ईज ऑफ डूईंग बिजनेस का अर्थ है कि वेश में कारोबार करने में कारोबारियों को कितनी आसानी होती है।

चिव कोई कंपनी भारत में कोई कारोबार शुरू करना चाहती है और उसे बहुत कठिन कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

☆ किसी वेश में कारोबार शुरू करने और उसे चलाने के लिए माहौल कितना अनुकुल है। भारत में विजनेस शुरू करना आसान नहीं है और ऐसे माहौल में भारत की रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है।







भारत में पर्यटन प्रोत्साहन एवं प्रबंधन

आजादी के बाद से ही भारत में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय किए गए जिसके अंतर्गत समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास पर जोर दिया गया।

इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन हो सके

> भारत के विभिन्न राज्यों में विशेषकर ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन देने एवं उनके समग्र प्रबंधन के द्वारा पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा एवं दशा देने हेतु नीतिगत कदम उठाए गए हैं।

पर्यटन धूमरहित उद्योग होने के कारण स्थानीय रचनात्मक वस्तुओं जैसे विभिन्न हस्तकला के उत्पादों एवं सेवाओं के साथ-साथ लोककला एवं मितव्ययी नवाचार को भी बढ़ावा देता है

पर्यटन ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के अलावा सामाजिक एकीकरण व गरीबी उन्मूलन में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

स्थानीय खेलकूद एवं गतिविधियां, जो पर्यटकों की शारीरिक एवं मानसिक मनोदशा को झकझोर कर पुनः उन्हें उन स्थलों को अत्यधिक अन्वेषण हेतु प्रेरित करती है।

ग्रामीण पर्यटनः स्थानीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ग्रामीण पर्यटन स्थानीय कला एवं इसके साथ-साथ ग्रामीण पर्यटन सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक-सार तक पहचान बनाने यानी 'लोकल दू ग्लोबल' प्रक्रिया में अत्यंत सहायक होता है कलाओं के आदान-प्रदान का महत्त्वपूर्ण साथन बनते हैं

ग्रामीण पर्यटन एवं आजीविका

पर्यटन का हमारे देश
 के सामाजिक-आर्थिक विकास
 के साथ गहरा संबंध है।
 पर्यटन के क्षेत्र में राजस्व-पूँजी
 का अनुपात अल्पधिक
 होता है

पर्यटन क्षेत्र में प्रत्येक दस
लाख रूपये के निवेश से प्रत्यक्ष
रूप से 47 नौकरियों व परोक्ष
रूप से 11 नौकरियों का
सजुन होता है

ण्यर्यटन पूँजी-प्रधान तो है ही पंरतु अधिक श्रम-प्रधान क्षेत्र होने के कारण, भारत जैसे विकासशील देशों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता भी रखता है

•पर्यटन, मुख्य रूप से न कोवल

सेवा क्षेत्र में आजीविका के अवसर का

सुजन करने में सहायक होता है अपितु यह

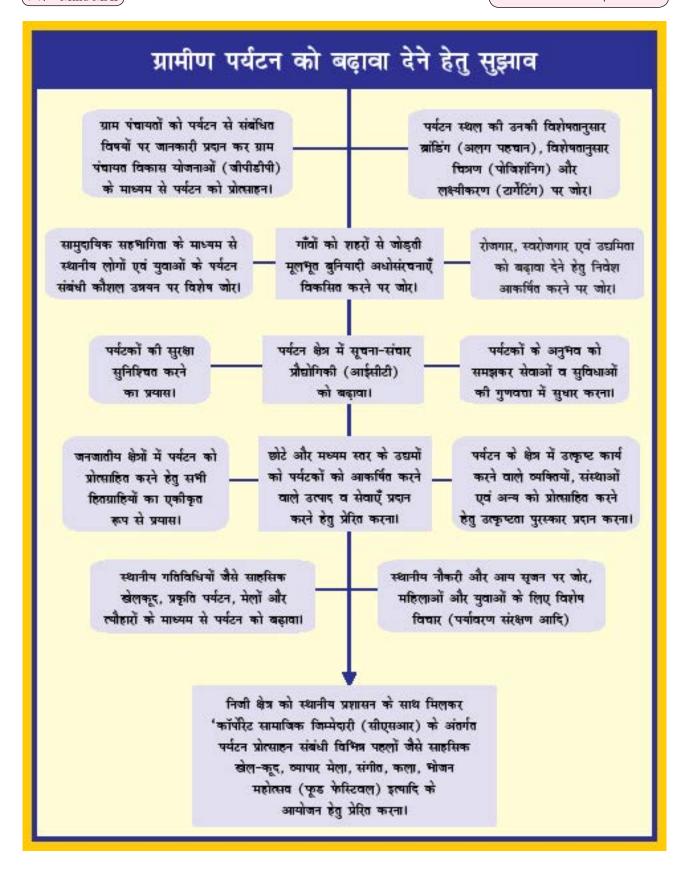
कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के साध-साध

विनिर्माण क्षेत्र के विकास में भी अपनी

महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है

• यह रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता को बढ़ावा देकर लगभग सभी क्षेत्रों में जैसे परिवहन, होटल एवं आतिथ्य, खुदरा व्यापार, कृषि, विश्तीय सेवाओं एवं अन्य सेवाओं के माध्यम से आजीविका के नए अवसर का सृजन करने में सहायक होता है

ण्यर्यटन किसी भी देश के सामाजिक एंव आर्थिक विकास में एक इंजन की भूमिका निभाने वाले स्रोत के रूप में कार्य करता है जिसके माध्यम से रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता और विदेशी मुद्रा से आय होती है



ग्रामीण पर्यटन का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- ◆भारत में 2011 की जगणना के अनुसार, वह क्षेत्र प्रामीण है जहाँ की जनसंख्या 10,000 से कम है।
- ◆इस सर्वे के अनुसार भारत में 7 लाख गाँव हैं जहाँ 74 प्रतिशत आवादी रहती है।
- ♦साथ ही, जनसंख्या का 62 प्रतिशत कृषि पर आधारित है।
 - ◆यह उन लोगों के लिए महत्त्वपूर्ण है जो पीडियों से शहर में रह रहे है और जड़ों से जुड़ना चाहते हैं।
- ◆'म्रामीण पर्यटन' वह पर्यटन है जो म्रामीण जीवनशैली, वहाँ की संस्कृति, परंपरा, लोक साहित्य, हस्तशिल्प और विरासत को वर्शाता है।
- ◆इसके अंतर्गत कृषि पर्यटन, पर्यावरणीय पर्यटन, एडवेंचर स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक पर्यटन शामिल हैं।
- ◆इसका मुख्य उद्देश्य लोगों का ग्रामीण जीवन से परिचय कराना और विभिन्न आयाम बताना है।
- ◆कम प्रवूषण, कम आबादी, प्राकृतिक वस्तुएँ, कम तकनीकी आदि कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं, जो लोगों को ग्रामीण पर्यटन की ओर आकर्षित करती हैं।
- 2017 में पर्यटन का सकल घरेलू उत्पाद में 3.7% प्रत्यक्ष योगवान था जो 2018 में 7.6% की वर से बढ़ा और वर्ष 2020 तक यह संभावना है कि यह सकल घरेलू उत्पाद का 3.9% हो जाएगा।
- चित्र पूर्ण योगवान की बात की जाए तो यह 2017 में 9.4 प्रतिशत था जो 2018 में 7.5 प्रतिशत की वर से बढ़ा (अनुमानित) और 2028 में सकल घरेलू उत्पाद का 6.9 प्रतिशत होने के संभावना है।
- रोजगार के वृष्टिकोण से वेखा जाए तो 5 प्रतिशत रोजगार केवल पर्यटन से आया है जो 2018 में 2.8% की वर से बढ़ा है और 2028 तक यह 2.1% की वर से बढ़ेगा।
- अर्थव्यवस्था और पर्यटन
- इस क्षेत्र की क्षमता का पता इस बात से चलता है कि 2017 में 1.08 करोड़
 विवेशी बात्री भारत आए जो 2016 की तुलना में 15.6 प्रतिशत अधिक हैं।
- 2016 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 161,36 करोड़ थी।
- 2017 में कुल मुद्रा आय 1,80,379 करोड़ थी जो 2016 की तुलना
 में 17 प्रतिशत अधिक थी।

4 निर्माण IAS

राज्यवार पहलु

ं िनन राज्यों में पार्परिक पर्वटन स्थल अधिक हैं वहाँ ग्रामीण पर्यटन स्थल कम हैं जैसे-राजस्थान और महाराष्ट्र। ○उत्तर-पूर्व के राज्यों में ग्रामीण पर्यटन स्थलों की संख्या अधिक है जिनका चुनाव पर्यावरणीय सुंदरता और इस्तशिल्प के आधार पर किया गया है।

अवह राज्य मुख्यत: महिला प्रधान हैं अत: पर्यटन स्थलों से इन महिलाओं की आमदनी में वृद्धि होती हैं।

○1987 में बंटलैंड रिपोर्ट में पहली बार, धारणीय विकास पर चर्च की गई और तब से संपूर्ण विश्व में सभी नीतियों का आधार बन गई। अर्तमान समय में चक्रवर्तों अर्थव्यवस्था पर चल रही चर्चा भी इसी बात पर है और ग्रामीण पर्यटन इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साधन है।

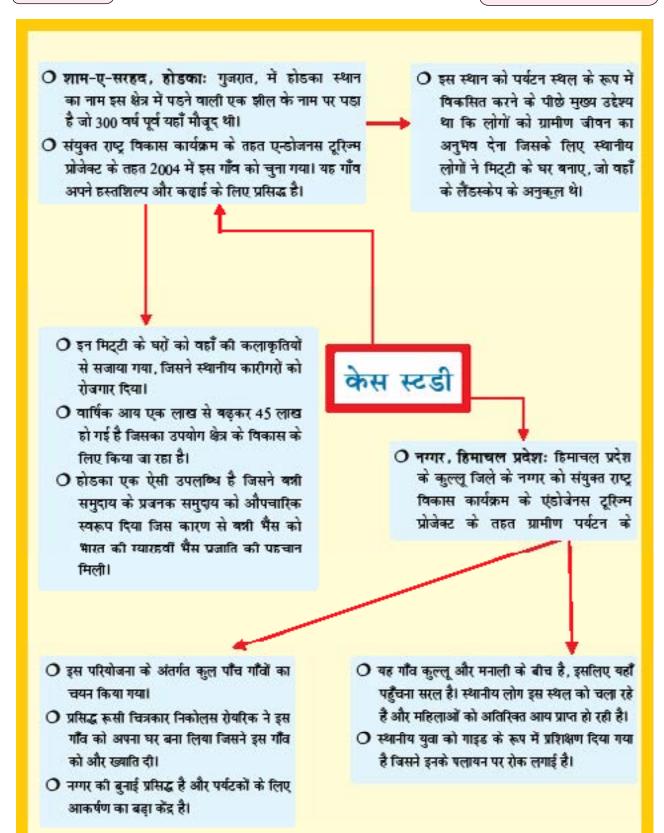
अभी स्थानों पर ग्रामीण पर्यटन में स्थानीय साधन, चाहे भीतिक हो अथवा मानवीय, के उपयोग पर जोर दिया जाता है। Oआधारभूत संरचना का तैयार होना बेहर आवश्यक है, खासकर भारत जैसे देशों में जहाँ आज भी सरकार सड़क, ऊर्जा, पेरजल आदि की बात कर ही है।

- Оग्रामीण पर्यटन के बहुत से लाभ हैं परंतु इसकी कुछ किमयां भी हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हानि पहुँचाती है। शहरी लोग अपने साथ तकनीक लेकर आते हैं जो गाँव की शांति और स्थिरता को भँग करती है।
- ○यह पर्वावरण के गंदे और प्रदृष्धित कर जाते हैं जिसका दुष्परिणाम गाँव के लोगों की सेहत पर पड़ता है कई बार स्थानीय साधन, स्थानीय लोगों की पहुँच से बाहर हो जाते हैं क्योंकि इन्हें पर्यटकों को आकर्षित करने का साधन मान लिया जाता है।

अप्रमीण क्षेत्रों की कार्यप्रणाली में परिवर्तन आ जाता है क्योंकि यह काम अस्थावी होता है, अत: कार्य लोकाचार को बिगाड़ देता है।

- िलोग अपने कार्व हेतु कृषि से पर्यटन में अस्थायी रूप से आते हैं परंतु इसके स्थानांतरण में मूल व्यवसाय कृषि नकारात्मक रूप से छोड़ दी जाती है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है।
- ७ मूल से ज्याज पर अधिक ध्वान दिया जाता है साथ ही, स्थानीय बाजार में मुद्रास्फीति होती है जो स्थानीय मांग को प्रभावित करती है जिसके दुष्परिणाम दूरगामी हैं।
- महिलाओं पर ग्रामीण पर्वटन के प्रभाव को देखना भी आवश्यक है।
- अमिहिलाएँ कार्यशक्ति का वह भाग है जो सामान्यत: सबसे अधिक कार्व करता है और जिसका भुगतान पृथक नहीं किया जा सकता।

Oअधिकांश केस स्टडी में यह पाया गया है कि महिलाएँ अपने घर का काम पूरा करते हुए व्यवसाय में योगदान देती हैं जो उनके उत्पर कार्यभार को बढ़ा देता है। Oयह सभी पर्यटन-स्थल स्थानीय समुदाय द्वारा चलाए जाते हैं जो स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक हैं पर महिलाओं पर भार में वृद्धि होतों हैं।





कृषि पर्यटनः- अनुकूल दशाएं, अपार संभावनाएँ संदर्भ भारत में कृषि केवल आजीविका का साधन नहीं, 🐨 अपेक्षाकृत कम लाभदायकता के कारण कृषक बल्कि जनमानस में रची-बसी एक पुरातन संस्कृति है। परिवारों में पुश्तैनी खेती से विमुख होने का सिलसिला शुरू हो गया। 'उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद चाकरी, भीख निदान' 🐨 औद्योगीकरण, शहरीकरण और आधुनिकीकरण की परंपरा वाले हमारे देश में कृषक को 'अन्नदाता' के वर्तमान दौर में कृषि क्षेत्र और जोत आकार और 'धरतीपुत्र' कह कर सम्मानित किया गया। संकुचित होने से कुफ्कों के आर्थिक-स्तर पर चोट पडी। 獅 मुख्य रूप से कृषि पर टिकी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए यह एक बुरा संकेत है, जो भविष्य में हमारे लिए अनेक कृषि और कृषि उद्यमों से इतर भी विचार-विमर्श सामाजिक-आर्थिक विषदाओं का कारण बन सकता है किया गया, लीक से हटकर कुछ नए अवसर इसलिए कृषि और कृषकों के आर्थिक उद्धार के मकसद तलाश करने की कोशिश की गई। से अनेक मंचों पर विमर्श प्रारंभ हुआ। कृषि और कृषि उद्यमों से इतर भी सोचा-विचारा गया, लीक से हटकर कुछ नए अवसर तलाश करने की कोशिश की गई। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है 'कृषि पर्यटन', जिसे 'एग्री-ट्रिन्म', 'एग्रो-ट्रिन्म' या 'फार्म ट्रिन्म' भी कहा जाता है। कुछ देशों में इसे 'एग्रीमेंट'का नाम दिया गया है।

7 निर्माण IAS

गाँव-गाँव पर्यटन

- भारत में कृषि आधी से अधिक जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन है, परंतु सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसका योगदान लगभग 17-18 प्रतिशत आंका गया है।
- कृषि की महत्ता इस तथ्य से भी आंकी जा सकती है कि देश के कुल भीगोलिक क्षेत्र के लगभग 43 प्रतिशत क्षेत्र पर बुआई कर खेती की जाती है।
- सन् 2011 की जनगणना के अनुसार देश में किसानों की संख्या लगभग 11.9 करोड़ है, जबकि लगभग 14.4
 करोड़ कृषि अमिक इस कार्य में सीधे जुड़े हैं।
- भारत में विश्व की लगभग सभी प्रकार की जलवायु
 और मिट्टी पाई जाती है, जिससे यहाँ अनुटी और
 अतुलनीय जैव-विविधता मौजूद है।
- भारत यह प्राकृतिक वरदान भारतीय कृषि को अपार संभावनाओं वाला क्षेत्र बनाता है।
- दूसरी ओर, पर्यटन हमारे देश का उभरता हुआ
 व्यवसाय है, जिसने सन् 2018 में देश के जीडीपी में
 9.2% और रोजगार में 8.1 प्रतिशत का योगदान किया।
- पर्यटन क्षेत्र में 6.9% की वार्षिक वृद्धि दर देखी जा रही है।
- सन् 2016 में देश में कुल 88.9 लाख विदेशी पर्यटक आए थे, जिनकी संख्या सन् 2017 में बढ़कर लगभग एक करोड हो गई, जो 15.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।
- पर्यटन की दृष्टि से विश्व के 136 देशों में भारत का
 40 वां स्थान है, परंतु पर्यटन की प्रतिस्पर्धी कीमतों के नजरिए से 10 वां स्थान है।
- इस विवेचन से स्पष्ट है कि भारत में कृषि और पर्यटन,
 दोनों ही क्षेत्रों में विकास तथा विस्तार की संभावनाएँ
 मौजूद है, जिनका लाभ 'कृषि पर्यटन' के उभरते उद्यम को
 मिल सकता है।
- भारतीय पर्यटन उद्योग में कृषि पर्यटन एक नए अवसर के रूप में सामने आया है, जिसका मुख्य कारण सामाजिक दशाओं में हो रहा बदलाय है।
- एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 35 प्रतिशत शहर निवासियों का गाँव में अब कोई संबंधी नहीं रह गया है और 43 प्रतिशत कभी गाँव नहीं गए हैं। इसका सबसे बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है।
- बड़े और आधुनिक स्कूल उन्हें कितवी ज्ञान तो दे रहे हैं, परंतु वे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि उनकी थाली में आने वाली रोटी किस तरह खेत से यात्रा शुरू करके उनकी रसोई तक पहुँचती है, गाय-भैस से दूध कैसे निकलता है।
- खेत-खिलहानों, ताल-तलैयों और पशु-पिक्षयों से उनका संबंध टूट गया है या कमजोर पड़ गया है।
- इस कारण शहर के निवासी अब अपना कुछ समय गाँव में बिताना चाहते हैं, भले ही वह पर्यटक के रूप में ही क्यों न आएँ।
- लगभग इन्हीं कारणों से वर्त्तमान समय में विदेशी पर्यटक भी हमारे गाँवों में आकर अपनी छुट्टियाँ बिताना चाहते हैं।



19

☐ कृषि पर्यटन को व्यापक और व्यावसायिक आधार देने के लिए आवश्यक है कि इसे सुनियोजित तरीके से प्रारंभ किया जाए।	□ सबसे पहले यह देखना चाहिए कि चुने गए स्थान या फार्म की देश के या कम से कम राज्य के विभिन्न भागों से अच्छी कनक्टिविटी हो।
☐ वह स्थान रेल या सड़क मार्ग से जुड़ा हो, यदि लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में हवाई अड्डा हो तो अधिक बेहतर होगा।	'फार्म स्टे' के आसपास होटल-रेस्तरां नहीं होते, इसलिए सुबह के नाश्ते से लेकर रात्रि के भोजन तक की व्यवस्था करना आवश्यक और कृषि पर्यटन का अभिन्न अंग है।
कुछ सुझाव	
 'मेन्यू' तय करते समय पंरपरागत भोजन को प्राथमिकता, दें, परंतु कुछ आधुनिक खान-पान भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि परिवारों में बच्चे भी होते हैं, जो आमतौर पर 'फास्ट फूड' पसंद करते हैं। कृषि पर्यटन में 'ओपन किचन' यानी खुली रसोई की व्यवस्था करना बेहतर हैं, ताकि पर्यटक साफ-सफाई को देख सकें और चाहे तो पांरपरिक व्यंजन खुद पकाने में अपने हाथ भी आजमा सकें। 	
 आनंद और मनोरंजन के अलावा यह भी आवश्यक है कि पर्यटक अपनी सुरक्षा के प्रति आश्यस्त हों। 	